06 March 2019

1. **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पी.एम.-एस.वाई.एम.) योजना**

- प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पी.एम.-एस.वाई.एम.) योजना की शुरूआत की है।

योजना के संदर्भ में जानकारी:-

- यह असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिनकी मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम है और जिनके पास आधार संख्या के साथ ही बचत बैंक खाता भी है।
- यह एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित योजना है जिसके अंतर्गत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपये की एक सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन मिलेगी।
- इस योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है।
- इस योजना में ग्राहक का योगदान 55 रूपए प्रतिदिन से लेकर 200 रूपए प्रतिदिन तक है, ग्राहक का योगदान उसकी आयु पर निर्भर करता है, जिसकी सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है।
- इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार भी लाभार्थी के पेंशन खाते में समान योगदान देगी।
- इसके अतिरिक्त इस योजना की एक खास विशेषता है कि यदि कोई ग्राहक बीच में योजना छोड़ना चाहता है तो ग्राहक को उसके द्वारा जमा की गई उसकी पूरी धनराशि वापस लौटा दी जाएगी।
- इस योजना को पूरे देश में सामान्य सेवा केंद्रो (सी.एस.सी.) के माध्यम से लागू किया जाएगा।

लाभ

- यह अनुमान है कि असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ मजदूर इस योजना का लाभ उठाएंगे, जो देश के कुल श्रमिकों का लगभग 85% हिस्सा है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –महत्वूपर्ण योजना

स्रोत-पी.आई.बी.

2. **अल नागाह 2019- भारत और ओमान के मध्य सैन्य युद्धाभ्यास**

- अल नागाह III युद्धाभ्यास, भारत और ओमान के मध्य द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास की श्रृंखला में तीसरा युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन ओमान में जबेल अल अख़दर पर्वत पर किया गया है।
- इस युद्धाभ्यास में अर्द्ध-शहरी पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर-कार्यकारिता को बढ़ाने के उद्देश्य से दोनो देशों की सेनाएं रणनीति, हथियार व्यवस्थापन और फायरिंग में विशेषज्ञता और अनुभव का विनिमय करेंगी।
- युद्धाभ्यास अल नागाहा III पहले दो संयुक्त युद्धाभ्यासों का अनुसरण करता है जो क्रमश: जनवरी, 2015 में ओमान में और मार्च, 2017 में भारत में आयोजित किए गए थे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत-पी.आई.बी.

3. **<u>राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (एन.ए.आर.एस.एस.) 2018-19</u>**

- यह सर्वेक्षण विश्व बैंक समर्थित परियोजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एस.बी.एम.-जी.) के अंतर्गत एक स्वतंत्र सत्यापन संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है।

सर्वेक्षण के निष्कर्ष:-

- इस सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ है कि ग्रामीण भारत में 96.5% परिवार ऐसे हैं जो शौचालय का उपयोग करते हैं।
- इस सर्वेक्षण ने पहले घोषित किए जा चुके और विभिन्न जिलों एवं राज्यों द्वारा ओ.डी.एफ. के रूप में सत्यापित किए जा चुके गांवो के 90.7% गांवों को दिए गए खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) दर्जे की भी पुन: पुष्टि की है।

संबंधित जानकारी

- सरकार का दावा है कि अक्टूबर, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम शुरू होने के बाद से 500 मिलियन लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया है, इस कार्यक्रम की शुरुआत के समय 550 मिलियन लोग खुले में शौंच करते थे और आज खुले में शौंच करने वालों की संख्या घटकर 50 मिलियन से भी कम रह गई है।
- इस मिशन के अंतर्गत ग्रामीण भारत में 9 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं।
- सरकार के अनुसार, 5 लाख से अधिक गांवों और 615 जिलों को ओ.डी.एफ. का दर्जा दिया गया है और इसके साथ ही 30 ओ.डी.एफ. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दर्जा दिया जा चुका है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

4. **<u>राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना</u>**

- विश्व बैंक और भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एन.आर.ई.टी.पी.) के लिए $ 250 मिलियन के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- यह परियोजना कृषि और गैर-कृषि उत्पादों के लिए व्यवहार्य उद्यम विकसित करके नई पीढ़ी की आर्थिक पहलों को अपनाने में ग्रामीण परिवारों की महिलाओं की मदद करेगी।
- यह परियोजना संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में महिलाओं के स्वामित्व वाले और महिलाओं के नेतृत्व वाले कृषि एवं गैर-कृषि उद्यमों को बढ़ावा देगी।
- यह व्यवसायों का निर्माण करने में भी उन्हें सक्षम बनाएगी जो वित्त, बाजार और नेटवर्क तक पहुंचने और रोजगार सृजन में उनकी मदद करता हैं।
- एन.ई.आर.टी.पी. अपने व्यक्तिगत और/ या सामूहिक रूप से स्वामित्व वाले और प्रबंधित उद्यमों के निर्माण के लिए स्टार्ट-अप वित्तपोषण विकल्पों सहित वित्त का उपयोग करने के लिए एक मंच बनाकर ग्रामीण गरीब महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यम विकास कार्यक्रमों का समर्थन करेगा।
- इसके अतिरिक्त यह दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के समन्वय में युवा कौशल विकास का भी समर्थन करेगा।
- यह परियोजना वर्तमान में 13 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

5. **<u>सात बैंको पर स्विफ्ट के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है।</u>**

- भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने वैश्विक मैसेजिंग मंच स्विफ्ट (SWIFT) से संबंधित विनियामक निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए सात वाणिज्यिक बैंकों पर जुर्माना लगाया है।

स्विफ्ट (विश्वव्यापी इंटरबैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी)

- स्विफ्ट, एक वैश्विक सदस्यीय-स्वामित्व सहकारी संस्था है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है।

- इसकी स्थापना वर्ष 1973 में 15 देशों के 239 बैंकों के एक समूह द्वारा की गई थी, जिसने सीमा पार से भुगतान की सुविधा के लिए एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संदेश सेवा और सामान्य मानकों को विकसित करने के लिए एक सहकारी उपयोगिता का गठन किया था।
- स्विफ्ट न तो अपने स्वामित्व में निधि रखता है न ही बाहरी ग्राहक खातों का प्रबंधन करता है।
- इसकी मुख्य भूमिका एक सुरक्षित हस्तांतरण प्रणाली प्रदान करना है, जो इस प्रकार है कि यह सिर्फ बैंक A के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं पता है कि बैंक A द्वारा बैंक B को भेजा गया संदेश पहुँच गया है।
- इसके बदले में बैंक B यह जानता है कि बैंक A के अतिरिक्त अन्य कोई भी बैंक मार्ग में इस संदेश को भेज, पढ़ अथवा बदल नहीं सकता है।
- बैंकों को वास्तव में संदेश भेजने से पहले जांचने की आवश्यकता होती है।

संबंधित जानकारी

पी.एन.बी. मामले में क्या हुआ था?

- स्विफ्ट ने बढ़ते साइबर हमलों के खिलाफ लड़ाई में ग्राहकों का समर्थन करने के लिए वर्ष 2016 की शुरुआत में ग्राहक सुरक्षा कार्यक्रम (सी.एस.पी.) की स्थापना की थी।
- पी.एन.बी. मामले में, इसकी सबसे बड़ी विफलताओं में से एक, स्विफ्ट और बैंक के समर्थित सॉफ्टवेयर के मध्य लिंक का गायब हो जाना था।
- इसने एक प्रमुख निकासी उपकरण के फर्जी उपयोग की अनुमति दी कि स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से दूसरे बैंक को निधि हस्तांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन अथवा ऋण प्रार्थना पत्र भेजना।

टॉपिक-जी.एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

6. **<u>परिवहन एवं विपणन सहायता (टी.एम.ए.) योजना</u>**

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग ने विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता (टी.एम.ए.) हेतु एक योजना को अधिसूचित किया है।

योजना के संदर्भ में जानकारी:-

- इस योजना का उद्देश्य कृषि उपज के माल और विपणन के अतंर्राष्ट्रीय घटक हेतु सहायता प्रदान करना है, जिससे ट्रांस-शिपमेंट के कारण विशिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात की उच्च लागत के नुकसान को कम करने और विशिष्ट विदेशी बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों के लिए ब्रांड पहचान को बढ़ावा देने की संभावना है।
- यह योजना विदेश व्यापार नीति (2015-20) में अनुकूलित रूप से शामिल की जाएगी।
- विदेश व्यापार नीतिके अनुसार संगत निर्यात संवर्धन परिषद के साथ पंजीकृत योग्य कृषि उत्पादों के सभी निर्यातकों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
- सहायता केवल तभी स्वीकार्य होगी यदि निर्यात के लिए किया गया भुगतान सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से निशुल्क विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है।
- यह योजना केवल ई.डी.आई. (इलेक्ट्रॉनिक डाटा विनिमय) बंदरगाहों के माध्यम से किए गए निर्यात के लिए स्वीकार्य होगी।
- इस योजना में हवाई और समुद्री मार्ग (सामान्य और बादबानी माल दोनो) द्वारा निर्यात के लिए माल ढुलाई और विपणन सहायता शामिल है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –महत्वूपर्ण योजना

स्रोत- टी.ओ.आई

7. **<u>फॉल आर्मीवॉर्म (एफ.ए.डब्ल्यू.) ने 50 से अधिक देशों में फसलों को संक्रमित किया है।</u>**

- एफ.ए.डब्ल्यू. से निपटने और इसे फैलने से रोकने के लिए सरकार किसानों के मध्य जागरूकता पैदा कर रही है और रसायनों का वितरण कर रही है।
- वर्ष 2016 की शुरुआत में, एफ.ए.डब्ल्यू. के उपभेदों को पहली बार नाइजीरिया में देखा गया था।
- एफ.ए.डब्ल्यू. मक्का, बाजरा, गेहूं, आलू, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, चारा, चावल, गन्ना और सब्जियों और कपास जैसी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण फसलों को नुकसान पहुंचाता है।
- एफ.ए.डब्ल्यू., जलवायु परिवर्तन के कारण पनपता है। इसका पूरा जीवन चक्र गर्म मौसम के दौरान 30 दिनों में पूरा हो जाता है। ठंडे मौसम के दौरान इसे पनपने में 90 दिन तक का समय लग सकता है।

फ़ॉल आर्मीवॉर्म (एफ.ए.डब्ल्यू.)

- यह एक कीट है जो अमेरिका के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मूल निवासी है।

- प्राकृतिक नियंत्रण अथवा अच्छे प्रबंधन के अभाव में यह फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।
- एफ.ए.डब्ल्यू. को पहली बार वर्ष 2016 के प्रारंभ में मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में पाया गया था और यह शीघ्र ही लगभग संपूर्ण उप-सहारा अफ्रीका में फैल गया था।
- जुलाई, 2018 में भारत और यमन में इसकी पुष्टि की गई थी।